अनिल क्षेत्रपाल न्यायधीश के सामने

कान्हा - अपीलकर्ता

बनाम

मांगे राम और अन्य - प्रतिवादी

आरएसए- 2007 का 2452

2 मार्च 2020

1. **पंजीकरण अधिनियम, 1908-** सिविल प्रक्रिया डिक्री को स्वीकार करना पूर्व पारिवारिक निपटान–पंजीकरण की आवश्यकता नहीं।

माना गया कि सिविल कोर्ट का फैसला एक पूर्व परिवार को स्वीकार करता है निपटान स्वामित्व के हस्तांतरण का एक साधन नहीं है और इसलिए, नहीं पंजीकृत होना आवश्यक है।

(पैरा 21)

2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–एस. 8–अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति वर्ग-1 के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा धारा 8–सहदायिकी का चरित्र खो देती है संपत्ति।

माना गया कि एक बार संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो गई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत, सहदायिकता समाप्त हो जाती है अस्तित्व में है और उत्तराधिकारियों के हाथ में संपत्ति नहीं रहती है सहदायिक संपत्ति.

(पैरा 20)

ए.के.खुब्बर, अधिवक्ता
अपीलकर्ता के लिए

अजय विजरानिया, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए

अनिल क्षेत्रपाल न्यायधीश

(1) प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने वर्तमान नियमित दायर किया है द्वारा प्राप्त तथ्यों की समवर्ती खोज के विरुद्ध द्वितीय अपील वादी-प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए नीचे की अदालतें (यहाँ) -मांगे राम को इस आशय की घोषणा के लिए कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और सिविल वाद संख्या में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भुगता गया निर्णय और डिक्री। 568 का 1995 दिनांक 19.7.1995 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निर्णय अवैध, शून्य है और शून्य और वादी और प्रोफार्मा के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है बचाव पक्ष। यह तर्क दिया गया है कि सहदायिक संपत्ति नहीं हो सकती प्रतिवादी के विरुद्ध पारित निर्णय और डिक्री के माध्यम से अलग कर दिया गया क्रमांक 2 और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में।

(2) इस न्यायालय के विचाराधीन निम्नलिखित प्रश्न हैं निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है कानून:-

(i) क्या संपत्ति प्राकृतिक उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत ए परिवार का सदस्य सहदायिक बना रहेगा संपत्ति।

(ii) क्या किसी सिविल कोर्ट की डिक्री पूर्व को स्वीकार करती है पारिवारिक निपटान को पंजीकृत करना आवश्यक है।

(iii) क्या एक दस्तावेज जो पूर्व को स्वीकार करता है पारिवारिक समझौता त्याग का एक कार्य है और इसलिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है.

(3) मामले के तथ्यों पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। यह परस्पर समझने के लिए एक वंशावली तालिका बनाना उचित होगा पार्टियों के बीच संबंध:-

रंजीत

|

| |

गंगा बिशन (8.7.1968 को निधन) बूटी

| |

करिया (पत्नी) कान्हा

|

| | | |

बेग राय (स) धीरू (स) रामानंद(स) निम्बो(ड)

|

श्रीमती. बरज़ी (पत्नी)

| | | |

मांगे राम उदय सिंह राज करण राजेश
(वादी)

(4) वादी-प्रतिवादी संख्या 1-मांगे राम धीरू का पुत्र है- प्रतिवादी क्रमांक 2 जबकि कान्हा प्रतिवादी क्रमांक है। 1. धीरू और कान्हा हैं चचेरे भाई-बहन क्योंकि उनके दादा एक ही थे और दोनों के पिता पार्टियां भाई-भाई थीं.

(5) प्रतिवादी क्र. जबकि 3, 4 और 5 धीरू के बच्चे हैं प्रतिवादी संख्या 6 धीरू की पत्नी है।

(6) धीरू का परिवार दो भागों में कृषि भूमि का मालिक था अलग-अलग गांव यानी गांव बादल तहसील चरखी दादरी और गांव दमकोरा, तहसील लोहारू। यह प्रतिवादी का मामला है कि धीरू वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ ग्राम दमकोरा में स्थानांतरित हो गया था मुकदमा दायर करने से लगभग 100 वर्ष पहले। यह रिकार्ड में भी आ गया है कि श्री धीरू ने कृषि भूमि और अन्य संपत्ति हस्तांतरित कर दी अपने चार पुत्रों अर्थात् मांगे के पक्ष में बादल गाँव में स्थित है राम, उदय सिंह, राज करण और राजेश। उपरोक्त परिवार निपटान को सिविल न्यायालय के माध्यम से मान्यता दी गई और स्वीकार किया गया 2.4.1990 को डिक्री पारित हुई। 2.4.1990 को पारित आदेश की प्रति निम्नानुसार निकाला जाता है:-

> "चूंकि मुकदमे के पक्षकार किसी भी मुद्दे पर विवाद में नहीं हैं तथ्यों और कानून का प्रश्न है और इसलिए, को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में स्वीकारोक्ति की गई अदालत में दर्ज किए गए उनके बयान में भी, मैं मुकदमे का फैसला करता हूं वादी को यह घोषणा करने के लिए कि वे इसके मालिक हैं प्रार्थना के अनुसार समान शेयरों में वाद भूमि का कब्ज़ा। नहीं लागत के अनुसार आदेश दें. तदनुसार डिक्री पत्र तैयार किया जाए। फ़ाइल भेज दी जाए।"

(7) श्री कान्हा प्रतिवादी क्रमांक 1-अपीलकर्ता ने यहां एक सिविल मुकदमा दायर किया नहीं। 568 दिनांक 17.7.1995 36 कनाल 14 मरला भूमि का दावा पारिवारिक समझौते और विभाजन/समायोजन के आधार पर। इस सूट में, धीरू प्रतिवादी नंबर 1 था. धीरू ने स्वीकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया उपरोक्त मुकदमे में वादी का दावा. धीरू गवाही में पेश हुए और एक बयान का सामना करना पड़ा कि वह वादी के दावे को स्वीकार करता है - उपरोक्त सूट में कान्हा. इसके अनुसरण में, विद्वान न्यायालय आया यह पाते हुए कि दोनों पक्ष मुद्दे पर नहीं थे और इसलिए, मुकदमे का फैसला सुनाया गया निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.7.1995 द्वारा।

(8) वादी-मांगे राम, उदय सिंह, राज करण और राजेश एक दस्तावेज़ निष्पादित किया जो पारिवारिक समझौते के रूप में है जिसमें यह स्वीकार किया गया कि मांगे राम को कोई अधिकार नहीं होगा। बादल गांव में भूमि का स्वामित्व या हित। इसके बाद मांगे राम सिविल सूट नं. दायर किया. 656 दिनांक 5.10.1986 की सत्यता को चुनौती देते हुए वाद संख्या में पारित निर्णय एवं डिक्री। 17.7.1995 के 568 पर निर्णय हुआ 19.7.1995. प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने अलग-अलग दायर किया मुकदमे का विरोध करने वाले लिखित बयान। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यह निवेदन किया धीरू अपने परिवार के साथ दमकोरा, तहसील गांव में स्थानांतरित हो गये थे लोहारू में लगभग 100 वर्ष पूर्व और राजाज्ञा के कारण भुगतना पड़ा एक समायोजन. दावा है कि पारिवारिक समझौता 10-11 को हुआ था वर्षों पहले और तब से कान्हा का कब्ज़ा बरकरार रहा मालिक के रूप में संपत्ति. मांगे राम को मुकदमा दायर करने का अधिकार भी था पूछताछ की. प्रतिवादी सं.2 से 6 ने अलग-अलग लिखित बयान दाखिल किए यह प्रस्तुत करते हुए कि वादी द्वारा दायर मुकदमा झूठा है और इसलिए, यह प्रस्तुत करते हुए बर्खास्त किये जाने योग्य है कि प्रतिवादी क्रमांक 2-धीरू था संपत्ति का पूर्ण स्वामी और एक पारिवारिक समझौते में इसका पतन हो गया था कान्हा के हिस्से में. यह दावा किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 2 धीरू के पास था वर्ष में ग्राम दमकोरा स्थित भूमि का वितरण पहले ही कर चुका है 1990 में मांगे राम और अन्य बेटों को और उसके बाद, जब मांगे राम- वादी ने एक परिवार से गांव बादल स्थित जमीन में अपना हिस्सा मांगा 16.5.1993 को समझौता हुआ और इस प्रकार मांगे का दावा हुआ राम संतुष्ट हुए और उन्होंने हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि की पारिवारिक समझौते का ज्ञापन.

(9) साक्ष्य में मांगे राम पीडब्लू3 के रूप में उपस्थित हुए। उसने स्वीकार किया पूर्व लिखना. डी-1 दिनांक 16.5.1993. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 110 बीघे भूमि का हस्तांतरण पारिवारिक बंदोबस्त के माध्यम से धीरू के पक्ष में किया गया था वादी सहित उसके पुत्र।

(10) विद्वान ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित कारणों को दर्ज करते हुए वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया है: -

> i) कि संपत्ति किसके हाथ में सहदायिक संपत्ति है धीरू जो उन्हें अपने पिता गंगा बिशन से विरासत में मिला था इसलिए, संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार है सहदायिक संपत्ति में धीरू को डिक्री झेलने का कोई अधिकार नहीं था कान्हा का पक्ष क्योंकि मांगे राम और प्रतिवादी क्र.3 से उक्त संपत्ति पर 5 का पहले से ही अधिकार था।
>
> ii) 19.7.1995 को पारित डिक्री बचने का एक उपाय है स्टाम्प शुल्क क्योंकि कोई पारिवारिक समझौता नहीं हो सका कान्हा और धीरू के बीच.
>
> iii) बही एक्स.डी1, दिनांक 16.5.1993 में लिखावट नहीं है साक्ष्य में स्वीकार्य है क्योंकि लेखन वर्तमान में दर्ज है और उदय के पक्ष में संपत्ति के हस्तांतरण के बराबर है सिंह. अत: पंजीयन कराना अनिवार्य है।

(11) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक संक्षिप्त निर्णय द्वारा सीखा था विद्वत् परीक्षण के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया अदालत।

<u>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण</u>

(12) अपीलार्थी-कान्हा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने किया प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में गंगा बिशन की मृत्यु 8.7.1968 को हुई। पर उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति धारा 8 के अनुसार प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा विरासत में मिली थी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के पक्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। की मृत्यु पर गंगा बिशन की संपत्ति का उत्तराधिकार बेग राज, धीरू और राम को मिला नंद, तीन बेटे, निम्बो - बेटी और क्रिया, विधवा गंगा बिशन. इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार हिंदू की धारा 8 छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने के लिए उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया है गंगा बिशन द्वारा, संपत्ति सहदायिक संपत्ति नहीं रहती है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1990 में डिक्री पारित होने के बाद यानी 2.4.1990 को और परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन हो गया, इसलिए, उसके बाद कोई सहदायिक अस्तित्व में नहीं था। उन्होंने आगे यह भी कहा Ex.D-1, बही में लेखन वास्तव में एक पारिवारिक समझौता है और इसलिए, वादी को संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है संयुक्त सहदायिक संपत्ति.

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा प्रस्तुत किया गया कि दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया है और इस न्यायालय को तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

<u>जाँच - परिणाम</u>

(14) पक्षों के तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इसमें कानून के प्रश्न तय किये गये हैं इस निर्णय की शुरुआत विचारार्थ है।
(15) इसमें कोई विवाद नहीं है कि धीरू का परिवार कहीं और चला गया था दाखिल करने से लगभग 100 वर्ष पहले ग्राम बादल से ग्राम दमकोरा सुविधाजनक होना। पिता धीरू ने दमकोरा गांव स्थित जमीन का बंटवारा कर लिया था उनके चार बेटों मांगे राम, राज करण के बीच 110 बीघे की जमीन है। उदय सिंह और राजेश. मांगे राम ने बंटवारा करने से पहले यह स्वीकार किया कृषि भूमि में से धीरू ने 30 बीघे जमीन भी बेच दी थी. यह भी अंदर नहीं है विवाद यह है कि जब गंगा बिशन की मृत्यु 8.7.1968 को हुई, तो संपत्ति का स्वामित्व किसके पास था गंगा बिशन को उनकी विधवा, तीन पुत्र और एक पुत्र विरासत में मिले बेटी। इस प्रकार गंगा बिशन का उत्तराधिकार हुआहिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार। इस संबंध में म्यूटेशन वर्ष 1968 में स्वीकृत किया गया था। की प्रति उत्परिवर्तन Ex.P-3 है, जो वादी द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है। इस प्रकार, एक बार के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सम्पत्ति हाथ लगी वर्ग 1 के उत्तराधिकारी, ऐसी संपत्ति सहदायिक नहीं बनी रहेगी संपत्ति। इस संबंध में पारित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है धन कर आयुक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कानपुर बनाम चंदर सेन 1 . भंवर बनाम पूरन 2 और उत्तम बनाम सौभाग सिंह 3 . उत्तम के मामले में जो निष्कर्ष निकला (सुप्रा) को निम्नानुसार निकाला जाता है :-

> “20. इसके लिए हमारे सामने कुछ अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया प्रस्ताव है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति वैसे ही बनी रहेगी एकमात्र जीवित सहदायिक के साथ, और यदि उसके एक पुत्र का जन्म हुआ है उसके बाद सहदायिक, संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी रहती है इस प्रकार, केवल इस तथ्य के आधार पर कोई अंतराल नहीं है एकमात्र जीवित सहदायिक है। धर्मा शामराव अगलावे बनाम पांडुरंग मिरागु अगालावे (1988) 2 एससीसी 126, शीला देवी बनाम लाल चंद, (2006) 8 एससीसी 581, और रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह (2013) 9 एससीसी 419, इस उद्देश्य के लिए उद्धृत किया गया था. इनमें से कोई भी निर्णय नहीं होगा अपीलकर्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगे ले जाएं कि किसी में भी नहीं उनमें से क्या अनुभागों के प्रभाव पर कोई विचार किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4, 8 और 19। कानून, इसलिए, जहां तक यह द्वारा शासित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है मिताक्षरा स्कूल, 2005 के संशोधन से पहले, कर सकता था इसलिए संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए:-
>
> (i) जब किसी पुरुष हिंदू की शुरुआत के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु के समय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में रुचि, उनकी रुचि संपत्ति में उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा सहदायिक के जीवित सदस्य (धारा 6 के अंतर्गत)।
>
> (ii) प्रस्ताव (i) के लिए, एक अपवाद अनुभाग में निहित है 30 अधिनियम की व्याख्या, यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ब्याज मिताक्षरा में एक पुरुष हिंदू की सहदायिकी संपत्ति है वह संपत्ति जिसका निपटान उसके द्वारा वसीयत या अन्य द्वारा किया जा सकता है वसीयतनामा स्वभाव.
>
> (iii) प्रस्ताव (i) में शामिल दूसरा अपवाद है धारा 6 के परंतुक में निहित है, जिसमें कहा गया है कि यदि ऐसा एक पुरुष हिंदू अपने पीछे एक महिला रिश्तेदार को छोड़कर मर गया था अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट या

कोई पुरुष रिश्तेदारउस वर्ग में निर्दिष्ट जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है उसके जीवित रहने वाले रिश्तेदार, फिर मृतक के हित में सहदायिक संपत्ति वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरित होगी या निर्वसीयत उत्तराधिकार, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

(iv) हिंदू पुरुष का हिस्सा निर्धारित करने के लिए सहदायिक जो धारा 6 परंतुक द्वारा शासित होता है, ए विभाजन ठीक पहले के कानून के क्रियान्वयन से होता है उनकी मृत्यु। इस बँटवारे में सभी सहदायिक एवं पुरुष हिंदू की विधवा को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता है।

(v) अधिनियम की धारा 8 के लागू होने पर, या तो एक पुरुष हिंदू की मृत्यु का कारण स्व-अर्जित छोड़ना संपत्ति या धारा 6 परंतुक के आवेदन द्वारा, जैसे संपत्ति केवल निर्वसीयत द्वारा हस्तांतरित होगी, नहीं उत्तरजीविता.

(vi) धारा 4, 8 और 19 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर अधिनियम, संयुक्त परिवार की संपत्ति के वितरण के बाद निर्वसीयतता के सिद्धांतों पर धारा 8 के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती विभिन्न व्यक्तियों के हाथ जो इसमें सफल हुए हैं वे संपत्ति को साझा किरायेदार के रूप में रखते हैं, संयुक्त के रूप में नहीं किरायेदार.

(16) इससे भी आगे, एक बार फिर, पारिवारिक समझौता हुआ/ धीरू द्वारा गांव स्थित 30 बीघे जमीन बेचने के बाद बंटवारा हुआ दमकोरा. मांगे राम, उदय सिंह राज करण और राजेश पुत्रगण स्व धीरू ने 110 की जमीन को लेकर धीरू के खिलाफ मुकदमा दायर किया था बीघे जिस पर धीरू ने दावा स्वीकार करते हुए लिखित बयान दाखिल किया वादी, जिसके परिणामस्वरूप निर्णय और डिक्री दिनांक 2.4.1990 आई। यह इस तथ्य को मांगे राम ने साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने पर स्वीकार किया था। इस प्रकार 1990 के बाद एक बार फिर विभाजन हुआ और उसके बाद कोई जोड़ नहीं हिंदू परिवार या सहदायिक संपत्ति मौजूद थी। इस प्रकार, दोनों न्यायालय इस निष्कर्ष को दर्ज करने में गलत थे कि संपत्ति बनी हुई है सहदायिक संपत्ति. धीरू धारा 8 के तहत संपत्ति का उत्तराधिकारी बना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अधिनियम के। इसलिए धीरू रुक नहीं रहा था संपत्ति एक सहदायिक संपत्ति के रूप में।

(17) इस पहलू की दूसरे कोण से भी जांच की जा सकती है। में 1993 में एक बार फिर धीरू के चारों बेटों के बीच पारिवारिक समझौता हुआ। उपरोक्त पारिवारिक समझौते में, जिसका निष्पादन स्वीकार किया जाता है मांगे राम, यह तय हुआ कि मांगे राम के पास कोई अधिकार, पदवी नहीं होगी या ग्राम बादल स्थित भूमि में हित। इसमें कोई शक नहीं, बाद में जमीन की कीमत का आकलन कर कुछ राशि का आदान-प्रदान किया गया। तथापि, ऐसे दस्तावेज़ को त्याग विलेख नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, यह है विशेष रूप से दर्ज किया गया कि दो भाइयों ने समझौता कर लिया है जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि मांगे राम को पास में कुछ जमीन मिलेगी अच्छी तरह से और स्थित भूमि में उदय सिंह के हिस्से के बदले में गांव बादल, उदय सिंह को एक निश्चित राशि का भुगतान किया गया। ऐसा समझौता है त्याग विलेख नहीं. दरअसल मांगे राम के पास पहले से कोई अधिकार नहीं था का सदस्य न रहने के बाद गाँव बादल की भूमि में पारिवारिक बंदोबस्त में 27 1/2 बीघे भूमि की प्राप्ति पर सहदायिकी। यहां तक कि धीरू के संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कोई सहदायिक अस्तित्व में नहीं था धारा 8 के अंतर्गत. आगे परिवार के

बीच संपत्ति के बंटवारे पर धीरू, मांगे राम के सदस्य यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें कोई पूर्व - संपत्ति में मौजूदा अधिकार धीरू के पास बचा है। नीचे के न्यायालयों के पास है यह निष्कर्ष दर्ज करने में भी गलती हुई कि कान्हा के पास पहले से कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, पारिवारिक समझौता और डिक्री 19.7.1995 को पारित हुई आवश्यक पंजीकरण. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, दोनों न्यायालयों ने 'परिवार' शब्द के संदर्भ में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है पारिवारिक समझौता. धीरू और कान्हा चचेरे भाई हैं। दादा दोनों पार्टियों में धीरू और कान्हा कॉमन थे यानी रंजीत। इसलिए, कान्हा और धीरू एक बड़े परिवार के सदस्य थे। जबकि परिवार के संदर्भ में परिवार के सदस्यों के अधिकारों की व्याख्या करना समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह आवश्यक नहीं है प्रत्येक सदस्य को अधिकार की कुछ झलक दिखानी होगी। इसमें सन्दर्भ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को न्यायालय बनाया जा सकता है न्यायालय, कृष्णबिहारीलाल बनाम गुलाबचंद 4। का पैरा 8 निर्णय इस प्रकार है:-

> “8. अगला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या विचाराधीन समझौते को एक के रूप में माना जा सकता है पारिवारिक विवादों का निपटारा. गौरतलब है कि पत्तोबाई के साथ लक्ष्मीचंद और गणेशीलाल भी थे समझौते के प्रमुख पक्ष थे पार्वती के पोते जो बुलाकीचंद की चाची थीं। पहले मुकदमे के पक्ष निकट संबंधी थे। पार्टियों के बीच विवाद किसी बात को लेकर था वह संपत्ति जो मूल रूप से उनके साझा स्वामित्व में थी पूर्वज अर्थात् छेदीलाल। एक समझौते के रूप में विचार करना पारिवारिक व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि पार्टियाँ हों समझौते के लिए सभी को एक ही परिवार का होना चाहिए। जैसा इस न्यायालय द्वारा राम चरण दास बनाम गिरिजा में देखा गया नंदिनी देवी, (1965) 3 एससीआर 841 पृष्ठ 850 और 851 पर = (एआईआर 1966 एससी 323 पृष्ठ 328 और 329 पर) "परिवार" शब्द पारिवारिक व्यवस्था के संदर्भ को समझा नहीं जा सकता व्यक्तियों का एक समूह होने के संकीर्ण अर्थ में कानून में उत्तराधिकार के अधिकार या अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है विवादग्रस्त संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा। यदि विवाद जो तय हो गया है वह निकट संबंधों के बीच एक है तो ऐसे विवाद का निपटारा एक परिवार के रूप में माना जा सकता है व्यवस्था-देखें रामचरण दास का मामला 1965-3 एससीआर 841 = (एआईआर 1966 एससी 323) (सुप्रा)”

(18) सहमति डिक्री के पंजीकरण की आवश्यकता के संबंध में,यह न्यायालय पहले ही ध्यान सिंह मामले में उपरोक्त मुद्दे की जांच कर चुका है अन्य बनाम मोहिंदर सिंह और अन्य 5।

(19) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि वर्तमान अपील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गई है अनुमति दिये जाने योग्य है तथा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नीचे की अदालतों को अलग रखा जाना आवश्यक है। समापन से पहले यहां पहले बनाए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है: -

(20) प्रश्न संख्या (i) के संबंध में यह माना जाता है कि एक बार संपत्ति हिंदू की धारा 8 के तहत वर्ग I के उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई है उत्तराधिकार अधिनियम, सहदायिकता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और संपत्ति हाथ में आ जाती है उत्तराधिकारियों की संपत्ति सहदायिक नहीं बनी रहेगी।

(21) प्रश्न क्रमांक (ii) के उत्तर में यह माना गया है कि सिविल न्यायालय पूर्व पारिवारिक समझौते को स्वीकार करने वाला डिक्री एक साधन नहीं है शीर्षक का स्थानांतरण और इसलिए, पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(22) प्रश्न संख्या (iii) के उत्तर में यह माना गया है कि एक दस्तावेज किसी पूर्व पारिवारिक समझौते को स्वीकार करना किसी विलेख के बराबर नहीं है त्याग या स्थानांतरण विलेख और इसलिए, इसकी आवश्यकता नहीं है दर्ज कराई।

(23) अपील की अनुमति दी गई।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समज सके और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंगरेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन कार्यावयन

के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

सुरेश पाल सन्धु